



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 1974/पौष 26, 1895

No. 26]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 1974/PAUSA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR

### ORDER

*New Delhi, the 16th January 1974*

**S.O. 39(E).**—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in any service in the State of Bihar connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, strike, in connection with any industrial dispute, in the said service for a period of six months.

N. P. DUBE, Addl. Secy.  
[No. F. S-42025/15/73-LR.I]

## अस संवालय

## आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1974

**का० आ० 39 (अ).—**यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः जनता को विद्युत् ऊर्जा के सम्भरण या ऐसे सम्भरण के प्रयोजन के लिए विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, संचयन या सम्प्रेषण से सम्बन्धित बिहार राज्य की किसी सेवा में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने के लिए, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उक्त सेवाओं में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त सेवा में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को तुरन्त प्रभावी रूप से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० एस-42025/15/73-एल० आर० 1]

[नि० प्र० दुबे, अपर सचिव ।